

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1349
दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन देना

1349. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) संतुलित आहार में दूध के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/की जा रही है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) जी हां। पशुपालन एवं डेयरी विभाग डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:

(i) दिसंबर 2014 से देशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया जा रहा है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यह योजना 2400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विभाग की संशोधित और पुनर्संरचित योजना के तहत जारी है।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना वर्ष 2014-15 से लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना का निर्माण करना है। यह योजना देश में डेयरी सहकारी समितियों के तहत नामित डेयरी किसान-सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है।

(iii) चल रही राज्य डेयरी सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठन योजना (एसडीसीएफपीओ) के तहत कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन के रूप में एकमुश्त सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक नया घटक शुरू किया गया था।

(iv) पहली बार सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा विस्तारित की है, जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिसमें स्वामित्व वाले/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान शामिल हैं, इस योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र हैं।

(v) भारत सरकार, डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की स्थापना सहित पशुधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की सुविधा के लिए 29110.25 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एचआईडीएफ) को लागू कर रही है।

(vi) राष्ट्रीय पशुधन मिशन गुणवत्तापूर्ण आहार एवं चारे की बेहतर उपलब्धता और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के जोखिम कवरेज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह योजना चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

(vii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) को खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और साथ ही डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की गई हैं।

(viii) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, डेयरी क्षेत्र सहित पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से करने के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा कर रहा है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन करता है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य के रखरखाव और राष्ट्र की पोषण सुरक्षा को बनाए रखने में दूध से जुड़े लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) मानव पोषण में दूध की भूमिका पर किसानों, डेयरी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और विशालतर आबादी के लाभ के लिए तकनीकी बुलेटिन प्रकाशित करके ज्ञान का प्रचार-प्रसार भी करता है।
